

असहमति पर सहमति: डोकलाम गतिरोध को समाप्त करना

साभार : द हिन्दू

29 अगस्त, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

कूटनीति ने डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन को अपने संबंध को बेहतर बनाने और कई विवादित मुद्दों को निपटाने के लिए नए उपायों को अपनाना होगा।

भारत और चीन द्वारा अलग-अलग की गयी घोषणाएं, जिसमें दोनों देशों ने कहा कि डोकलाम में तैनात की गयी सेना अब हटा ली गई है, एक स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि पिछले 10 हफ्तों से दोनों देश एक-दूसरे पर आरोप पर आरोप लगाये जा रहे थे। नयी दिल्ली द्वारा इस मामले के सन्दर्भ में दिए गये बयान से यह मालूम पड़ता है कि चीन द्वारा की जा रही नफरतभरी बयानबाजी के सिलसिले में दिल्ली की राजनयिक उपायों को अपनाने की नीति काफी सटीक थी। इसके विपरीत, चीन ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने विवादित डोकलाम पठार से अपनी सेना वापस ले लिया था, जबकि चीनी सैनिकों ने इस इलाके पर गश्त जारी रखा है, जो बीजिंग को इसे शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अलग-अलग संस्करणों और अधि क जानकारी की कमी के कारण कई सवाल बेमतलब की शर्तों के साथ अभी भी अनुत्तरित हैं। लेकिन तथ्य यह है कि दोनों देश बयान जारी करने में सक्षम हैं, भले ही वे अपने घरेलू दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हों, जो यह सुझाव देते हैं कि राजनयिक बातचीत में, प्रत्येक ने दूसरे की बाधाओं को ध्यान में रखा है।

वैसे इस मामले में दोनों देशों की मीडिया भी आगे बढ़-चढ़कर भाग ले रही है। भारत में चल रहे खबरों में यह कहा जा रहा है कि डोकलाम के मुद्दे पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और कुछ ने इसे चीन के लिए शर्मिन्दगी कहा है। दूसरी ओर सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक चीन ने मौके पर जाकर जायजा लिया और पुष्टि की कि भारत उस इलाके से अपने सैनिक और साजोसामान हटा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि डोकलाम को लेकर शांतिपूर्ण समझौते तक पहुंचने में चीन ने एक जिम्मेदार ताकत के तौर पर बर्ताव किया। एक दूसरे पर असंगत बयान जारी करते हुए दोनों पक्ष वर्तमान असहमति पर सहमत हो गये। इस संघर्ष विराम का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरह से दोनों देश अपने जिद पड़ अड़े हुए थे, इससे युद्ध की संभावना बढ़ गयी थी। वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई दिल्ली और बीजिंग ने भूटान सरकार की इच्छाओं

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न

1. दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भू-भागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (2014)
2. 'मोतियों के हार' (द स्ट्रिंग ऑफ पर्स) से आप क्या समझते हैं? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सामना करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। (2013)



का सम्मान किया, जो खुद इस विवाद का अंत इसके और अधिक बढ़ने से पहले चाह रहा था।

डोकलाम के फैसले का निपटारा होना काफी सुखद है और यह उस वक्त हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह बाद चीन की यात्रा करेंगे और 3 सितंबर को जियामेन में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देंगे। दूसरे शब्दों में, भारत चाहता था कि डोकलाम में 16 जून के पहले की स्थिति फिर कायम हो, लेकिन चीन वहां सड़क निर्माण या कोई दूसरा बदलाव करने की कोशिश न करे। दोनों देश इस बात को लेकर भी बेहद सतर्क थे कि दोनों के सैनिक एक दूसरे के खिलाफ कभी हथियार तानकर न खड़े हों। यही वजह है कि तनाव चरम पर होने के बावजूद सीमा पर एक गोली नहीं चली। यह इस बात का साफ इशारा था कि दोनों देश इस विवाद को अगले पड़ाव पर नहीं ले जाना चाहते। श्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद, राजनयिकों को कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए बंद पड़े नाथु-ला मार्ग को फिर शुरू करने के संबंध में प्रयास और नए उपायों को अपनाया चाहिए।

गतिरोध के दौरान चीन से दिए गए वक्तव्य से संकेत मिलता है कि यह वर्ष 2012 में विशेष प्रतिनिधि वार्ता से प्राप्त लाभों को स्वीकार नहीं करता है और न ही यह बातंग-ला के पास भारत-भूटान-चीन त्रिकोणीय जंक्शन को मानते हुए कोई बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सिक्किम की सीमा तय नहीं करता है और दोनों पक्षों को आगे बढ़ने से पहले इस तरह के मूलभूत मुद्दों पर समझौते के कुछ आलोक में आगे बढ़कर बातचीत करनी होगी। भारत और चीन को वर्ष 2013 की सीमा रक्षा सहयोग समझौते की भावना को याद करते हुए बेहतर संबंध के निर्माण के लिए विचार करना चाहिए, जहाँ दोनों देशों 3,488 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हुए भविष्य के विकास के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं। देखा जाये तो पिछले ढाई महीनों में जो कुछ भी हुआ है वह किसी सबक से कम नहीं है, साथ ही सेना प्रमुख बिपिन रावत ने रविवार को कहा कि भारत अब 'एक और डोकलाम' जैसे विवाद के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए, जब-जब इसके उत्तरी पड़ोसी के साथ तनाव की बात आती है, तो भारत को "सबसे अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए और सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए।"

इससे संबंधित तथ्य

- डोकलाम पठार भारत, चीन और भूटान के बीच की सीमा के त्रिकोण पर है। सीमाओं को चीन के जिगेज (शिगात्से) प्रांत में भारत के सिक्किम और यदोंग काउंटी द्वारा साझा किया जाता है।
- सदियों से, डोकलाम पठार भूटानी चरवाहों के लिए एक शांत चराई स्थल रहा है।
- चीन का दावा है कि यह उनके यदोंग काउंटी का एक हिस्सा है।
- यह चीन और भूटान के बीच तीन विवादित क्षेत्रों में से एक है। दूसरे दो जाकलंग और पासामुंग हैं।
- डोकलाम पठार 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

ऐतिहासिक विचारों से

- भारतीय स्वतंत्रता से पहले, 1890 सिक्किम-तिब्बत कन्वेंशन के माध्यम से अंग्रेजों ने चीन और तिब्बत के साथ सीमाओं का निपटारा किया था।
- 1890 सिक्किम-तिब्बत कन्वेंशन ने कहा कि सीमा भूटान फ्रंटियर में माउंट गीपामोकी में शुरू होती है और नेपाल क्षेत्र से मिलने के लिए जल-भाग क्षेत्र (वाटरशेड क्षेत्र) से ऊपर होता है।
- 1962 से, चीन ने डोकलाम पर भूटान के क्षेत्रीय दावों पर निरंतर विवाद किया है।



डोकलाम विवाद क्या है?

- चीन का कहना है कि त्रिजंक्शन दक्षिण की ओर माउंट गीपामोकी (बटांग ला के पास) पर होना चाहिए।
- हालांकि, भूटान का दावा है कि डोकलाम पठार भूटान का एक अभिन्न हिस्सा है और चीन बलपूर्वक भूटान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।
- चीन चाहता है कि भारत और भूटान को 1890 सिक्किम-तिब्बत कन्वेंशन का पालन करना चाहिए।
- भारत ने उत्तर दिया कि ब्रिटिश इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर करते समय सीमाओं की बजाय व्यापार में रूचि रखते थे।
- चीन ने बाद में 1890 के सम्मेलन का समर्थन करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने चीनी समकक्ष से लिखे एक पत्र दिखाया। भारत ने कहा कि चीनी 10 पेज के एक पत्र से सिर्फ एक पंक्ति का हवाला देते हुए बयान जारी

कर रहे हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि अक्सर चिन क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और मैकमोहन लाइन सीमा है। उन्होंने पूछा कि चीन इससे सहमत क्यों नहीं है?

- भूटान ने पुष्टि की कि यह कभी 1890 सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं था और उसके पास सार्वभौम अधिकार हैं।
- विवाद 8 जून की रात शुरू हुआ, जब चीन ने डोकलाम में एक पैतरेबाजी शुरू की।
- चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने चुपके से पठार में चले गए और 2 बंकरों को हटा दिया कि भूटान कभी-कभी गश्ती (भारत द्वारा निर्मित) के लिए इस्तेमाल करता था।
- 16 जून को, चीनी बुलडोजर्स और रोड रोलर्स ने रॉयल भूटान आर्मी (आरबीए) के विरोध का सामना किया। भूटान ने भारतीय मदद के लिए पूछा 2 दिन बाद भारतीय सेना ने चीनी प्रवेश को और आगे बढ़ने से रोक दिया।
- तब से, एक गतिरोध रहा है जहां सभी दलों ने अपनी स्थिति रखी है।

डोकलाम के सामरिक महत्व?

चीन के लिए

- चीन को चुम्बी घाटी को मजबूत करना है
- चुम्बी घाटी चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पास ल्हासा-बंगाल राजमार्ग है जो नाथुला से गुजरती है।
- चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि करना चाहता है। हाल के वर्षों में, चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर रहा है जो काफी तोपखाने बंदूकें, हल्के टैंकों और भारी वाहनों को ले जाने में सक्षम है।
- चीन विवादित क्षेत्रों में स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण की रणनीति का उपयोग करता है और बाद में यह दावा करता है कि क्षेत्र में कोई विवाद नहीं था। उदाहरण के लिए- दक्षिण चीन सागर (चीन ने पार्सल द्वीप पर साशा नामक एक शहर विकसित किया था)।
- चीन ने ल्हासा से यादों तक के एक 700 किमी लंबी राजमार्ग का निर्माण किया, जिसकी यात्रा में केवल 8 घंटे का समय, गंगटोक को नाथुला तक 50 किलोमीटर और लगभग 4 घंटे लगते हैं।



भारत के लिए

- भारत को अपने 27 किमी लंबे सिलीगुड़ी गलियारे (जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है) की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सड़क के द्वारा उत्तर-पूर्व भारत के साथ भारत की मुख्य भूमि से जुड़ने का एकमात्र मार्ग है।
- भारत का भूटान के साथ बहुत मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और इसलिए, यह भूटान को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
- क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का सामना करने के लिए, भारत को डोकलाम क्षेत्र में मजबूत दबाव डालना जरूरी है, क्योंकि चीनी यहां कमजोर हैं और यह सशस्त्र संघर्षों के दौरान चीन में प्रवेश करने के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग है।
- चुम्बी घाटी में चीनी उपस्थिति का सामना करने के लिए भूटान में 'हा' पर भारत में एक ब्रिगेड तैनात किया गया है।

इस गतिरोध के परिणाम?

- चीन ने कैलाश मानसरोवर की वार्षिक भारतीय तीर्थ यात्रा को रोक दिया।
- चीन ने कोलंबो और कराची में जहाजों की डॉकिंग करके भारत पर दबाव डालने के लिए हिंद महासागर में नौसेना निगरानी में वृद्धि की। यद्यपि चीन का कहना है कि जहाजों के कार्यों जैसे विरोधी चोरी, हिमोग्लोग्रफ, सागर विज्ञान, संयुक्त नौसेना अभ्यास और ओबोर दोस्ती हैं।

भारत और चीन के बीच अन्य विवाद?

भारत और चीन के पास विभिन्न मुद्दों जैसे कि:

- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में सीमा विवाद
- पश्चिमी-अक्साई चिन भारत द्वारा दावा किया।
- मध्य-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में चीन के साथ मुख्य रूप से वाटरशेड पर सीमाएं हैं। उत्तराखंड में सिक्किम और बारहोटी चराई के पास भूटान की त्रिज्या जैसे अंतर के कुछ क्षेत्र हैं।
- पूर्वी-अरुणाचल सीमा विवाद चीन तवांग क्षेत्र के साथ लगभग सभी अरुणाचल प्रदेश का दावा करता है।
- भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के खिलाफ विरोध किया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से गुजरता है जो कि भारत का अभिन्न अंग है
- चीन भारत के एनएसजी सदस्यता के खिलाफ है।
- एक आतंकवादी के रूप में डीवक अजहर को घोषित करने के लिए चीन का वीटो
- चीन के नियमित एलएसी उल्लंघन 2013 में इसी तरह की 3 सप्ताह की स्थिति जब चीन ने डेपसैंग प्लेन्स में एक अस्थायी शिविर बनाया था।
- करीब 50 साल पहले डोकलाम में भी इसी तरह की स्थिति सामने आई थी।



क्या युद्ध होगा? आगे का रास्ता

- भारत और चीन सबसे निश्चित रूप से युद्ध के परिणामों को जानते हैं और इसलिए इससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा, गतिरोध आम तौर पर युद्ध के लिए नहीं ले जाते हैं और वह भी एक छोटे से क्षेत्रीय मुद्दे पर।
- भारत और चीन दोनों ही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और विकासशील देशों में सबसे बड़ी हैं, लेकिन गरीबी के मुकाबले अब भी एक बड़ी आबादी है।
- चीन के निर्यात में कमी आई है और इसकी अर्थव्यवस्था धीमा कर रही है।
- चीन ने OBOR और मैरीटाइम सिल्क रूट में बहुत पैसा और मानवशक्ति का निवेश किया है। युद्ध में शामिल होने से बड़ी परियोजनाओं, संसाधनों और वित्तीय स्थिति डगमगा जाएगी।
- भारत इस तथ्य से वाकिफ है, इसलिए वह इस तरह के संघर्षों से दूर रहना चाहता है।
- गठबंधन सरकारों के साथ कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के कारण यह कमजोर था, जिससे सर्वसम्मति की कमी आई थी।
- यह पहला गतिरोध नहीं है और न ही यह अंतिम होगा।
- संबंधित देशों (भारत-चीन-भूटान) के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आवश्यक हैं। चीन एकतरफा यह हल नहीं कर सकता।

संभावित प्रश्न

हाल ही में भारत और चीन ने डोकलाम क्षेत्र में व्याप्त सीमा विवाद को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होने की संभावना बढ़ गयी है। इस कथन के संदर्भ में भारत के संतुलित कूटनीति की चर्चा करते हुए बताये कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाना अपेक्षित है? चर्चा कीजिये।